

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 17 अंक 179

नई पहल से मिलेगी मदद

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को दो योजनाओं को मंजूरी दी और इनके लिए 14,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ईवी को प्रोत्साहन देना जरूरी है।

दो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवायलिंग इन इन्वेस्टिव व्हीकल एवॉल्यूशन (पीएम ई-ड्राइव) योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो अगले दो वर्षों में भारत एडवांस्ड इंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइड्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) को प्रोत्साहित करेगी। फेम को शुरुआत 2015 में 900 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी की मदद से की गई थी। इस योजना का दूसरा संस्करण जो नए वित्त वर्ष समाप्त हुआ अगले 11,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। उम्मीद है कि नई योजनाएं देश में ईवी को अपनाए जाने की दिशा में मददगार होंगी और पिछली पहलों की कामयाबी को आगे ले जाएंगी।

यूक्रेन की आर्थिक सहायता प्रोडेल-डीजल इंजन की तुलना में अधिक होती है इसलिए उसे अनगुना के लिए राश्ट्रीयकृत समर्थन जारी माना जाता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना की मदद से 24.7 लाख इलेक्ट्रिक टोपडिया वाहन, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक लिफ्टिया वाहन और 14,028 ई बसों की मदद हो सकती है जिन्हें करीब 3,679 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक ट्रेलर्स को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रत्येक की राशि आवंटित की गई है जबकि 200 करोड़ रुपये का आवंटन 74,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए किया गया है। इसके अलावा पीएम-इंबेस सेल-चेमेट सिस्मुरिटी मैकेनिज्म (पीएमएस) योजना के लिए 3,435.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण से ई बसों की खरीद और संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगी। योजना के तहत चालू वर्ष से लेकर 2028-29 तक 38,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जानी हैं। योजना के तहत शुरुआती दिने अगले 12 वर्षों तक बसों के परिवहन को पीएमएस करेगी।

इलेक्ट्रिक टोपडिया वाहन की मदद के अलावा इस बार वॉल्यूमिक स्तर पर ईवी को अपनाए पर भी जोर है। उदाहरण के लिए इस बार इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वॉल्यूमिक वाहन पर ध्यान देना समझ में आता है। वॉल्यूमिक वाहन अधिक मूल्यवान होते हैं जबकि ईवोई वॉल्यूमिक वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर राजधानी में अधिक इलेक्ट्रिक ट्रक माल लेकर आगे तो इससे काफी राहत मिलेगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक बसें भी देश के कई शहरों के वातावरण के कारण होने वाला प्रदूषण कम करेगी क्योंकि वे डीजल से चलने वाली बसों का स्थान लेंगी। सार्वजनिक परिवहन को बजट समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से अधिकवांश बसें हैं और इस स्थिति में नहीं है कि वे अहम निवेश कर रहे हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि उनका योगदान सीमित रहे। वॉल्यूमिक स्टेशन पर ध्यान देना भी जरूरी है। इसी समाचार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक ईवी चार्जिंग कंपनी ने भारतीय ड्राक सेवा के साथ मिलकर इंदौरवाह के एक ईवी स्टेशन में ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। ऐसे और प्रयासों की बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डाक पर ध्यान: शहरों में प्रमुख स्थानों पर मौजूद ई और वहां उपलब्ध जमीन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना उपयुक्त हो सकती है।

पीएम ई-ड्राइव योजना में नई विशेषता होगी खरीदारों के लिए प्रारंभिक प्रमाणित ई-वाटर। खरीदारों को वे वाटरच भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा और खरीदार को इस पर हस्ताक्षर करके डीलर के पास जमा करना होगा। डीलर पर हस्ताक्षर करके मांग संबंधी प्रोत्साहन पाने के लिए अपलोड करेगा। यह पहल वास्तविक लाभार्थी को स्थिति करने में मदद करेगी लेकिन बढ़ा सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि एलेक्शन में चुनाव रूप से काम करे और जो जल्दी स्थानांतरित हो सके। इसमें मांग और देरी से डीलर प्रमाणित हो सकते हैं और ईवी को विक्रय पर असाद पड़ सकता है। सफल शुरुआत के लिए सरकार को स्वदेशीकरण और मूल्य सीमा तक इनके जैसे मुद्दों से सावधानी से निपटना चाहिए। पिछली योजना को इन विषयों में प्रभावित किया था।



अमरा मेल्टी

बजट में बढ़ती जानकारी और राजकोषीय सूझबूझ

इस वर्ष के बजट में एक नया वक्तव्य शामिल किया गया है, जो पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। विस्तार से बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को 2024-25 का बजट पेश किया और संसद ने उसे 8 अगस्त को मंजूरी दे दी। इस बजट में वित्त मंत्री ने एक नई और अहम जानकारी दी, जिसकी लगभग अनदेखी ही कर दी गई। यह जानकारी या खुलासा बजट के व्यवस्थापक के वक्तव्य क्रमांक 27-ए में दिया गया है।

इसे उसी दस्तावेज में शामिल वक्तव्य क्रमांक 27 समझने की भूल न करें, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह निपटारा जाने बॉन्ड और राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएफ) से उधार लेकर चलाई जा रही योजनाओं और धनराशियों का उल्लेख होता है। इसमें बाद में सरकारी खजाने से चुकाना जाता है। यह अलग बात है कि पिछले दो वर्षों में सूझबूझ के साथ हो रहे राजकोषीय प्रबंधन के कारण 2021-22 के बजट से ऐसे उधार या बॉन्ड का सारा नहीं बना पड़ा।

किंतु वक्तव्य 27 को व्यवस्थापक मंत्री ने 2021-22 तक की गई राजकोषीय गलती

की याद दिलाता है। ध्यान रहे कि बॉन्ड और एनएसएफ से लिए गए उधार को राजकोषीय जबाबदारी और बजट प्रबंधन (एफएआरबीएम) अभिनियम के तहत सरकारी कर्ज का हिस्सा माना जाता है। दूसरे शब्दों में उनकी मदद लेने से सरकार को वास्तव में हुए राजकोषीय घाटे पर पंच पड़ जाता है।

इससे भी बुरी बात यह है कि मार्च 2019 तक के बजट में इन बॉन्ड या उधार का कोई जिक्र नहीं किया गया था। 2019-20 के बजट में पहली बार व्यवस्थापक वक्तव्य क्रमांक 27 दिखाया गया जिसमें वक्तव्य क्रमांक 27 दिखाया गया। इसके साथ ही ऐसे मामलों में पारदर्शिता में संशय में जागरूकता बढ़ी। अगले दो सालों में वित्त मंत्रालय ने सचेत अगले वित्त में कि ऐसे बॉन्ड और उधार की कम से कम मदद ली जाए। 2022-23 में यह मदद लेनी बंद भी कर दी गई।

2016-17 से 2021-22 तक छह वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने बॉन्ड और एनएसएफ से कुल 4.61 लाख करोड़ रुपये एनएसएफ

उधार से आए थे और बॉन्ड की हिस्सेदारी करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये थी। परंतु पिछले दो वर्षों में सरकार ने इस रकम का उपयोग से निपटान किया और एनएसएफ का पूरा जूरा चुका दिया। अब सरकारी खजाने के केवल 1.37 लाख करोड़ रुपये को देवदारी बची है। यह राजकोषीय सूझबूझ सहायक है।

तकरीबन ऐसा ही समझदारी और पारदर्शिता दिखाते हुए 2024-25 के बजट दस्तावेज में पहली बार वक्तव्य क्रमांक 27-ए पेश किया गया जिसमें युनियन सरकारी कंपनियों द्वारा बजट से जुटाए गए संपत्तियों का ब्योरा शामिल है। ये कंपनियां हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएसएआई) और इंडियन रेलवे फार्मल कार्पोरेशन (आईआरएफसी)। इन दोनों कंपनियों द्वारा जुटाए गए संसाधन देवदारी नहीं हैं, लेकिन एफआरबीएम अभिनियम के तहत उन्हें केंद्र सरकार का कर्ज नहीं माना जाता है। फिर भी वित्त मंत्रालय ने इन उधारों को अतिरिक्त जानकारी के रूप में सार्वजनिक करवा रखा। इससे पता चलता है कि वित्त

मंत्रालय राजकोषीय सूझबूझ को किन्तु गंभीरता के साथ ले रहा है।

उदाहरण के लिए एनएसएआई की स्थानांतरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अभिनियम के तहत की गई थी। यह बाजार से धन उधार लेता है और टोल सड़क तथा अन्य प्रकार की आवस से देता चुकता है। इसी प्रकार आईआरएफसी भारतीय रेल के साथ पूरे वाली अपनी व्यवस्था के जरिये धन जुटाती है ताकि रेलवे की रोलिंग स्टॉक की जरूरतें पूरी की जा सकें।

इसमें केंद्र के खजाने के लिए वित्तीय जोखिम साफ नजर आते हैं। अगर एनएसएआई अपना कर्ज चुकाने के लिए टोल से ध्यान कर्माई नहीं कर पाया तो उसे उधारने के लिए केंद्र सरकार को ही आना होगा। इसका बोझ सरकारी खजाने पर ही पड़ेगा। इसी तरह आईआरएफसी धन को कमी के कारण बॉन्डधारकों की रकम नहीं दे पाए या कर्ज नहीं चुका पाए तो उसकी भरपाई रेल मंत्रालय को ही करनी होगी। अगर एनएसएआई और आईआरएफसी को बकाया देवदारी तैजो से बढ़ती है तो जोखिम और अधिक हो जाएगा। 2019-20 में एनएसएआई और 2020-21 में आईआरएफसी की देवदारी बढ़ती हुई हम देख ही चुके हैं। 2013-14 में एनएसएआई की बकाया देवदारी 23,356 करोड़ रुपये थी, जो 2019-20 में नौ गुना बढ़कर 2.48 लाख करोड़ रुपये हो गई। आईआरएफसी की बकाया देवदारी 2013-14 के 76,539 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 4.09 लाख करोड़ रुपये हो गई। इनके कुछ वर्षों में दोनों की बकाया देवदारी में जाफे की गति काफी गंभीर हुई है और उनकी सालाना जमा अतिरिक्त उधारी भी बढ़ी है। इसमें संदेह नहीं है कि बजट दस्तावेज में शामिल करने से इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन लोगों को सावधानी बताने का संदेश मिलेगा, जो अगले चलकर केंद्र में लोक वित्त संचालित हैं।

सावधानी का संदेश आवश्यक है क्योंकि अतीत में अक्सर सरकारी खजाने को हुए वास्तविक घाटा छिपाने के लिए राजकोषीय बाजीगरी करती रही है। 1987 में अपना इतिहास लिखते हुए करते हुए राजीव गांधी ने तैरते हुए मंत्रालय में निजुद अतिरिक्त रकम को खामोशी से सरकार को ब्योरा में शामिल कर लिया था। यह घाटे को कम दिखाने का चतुर्धा परा लेकिन राजकोषीय दृष्टि से नासमझी परा कदम था। कई वर्ष बाद संयुक्त प्रतिपक्षीय गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री पल्लिअन चिंदंबरम और किन्तु के बाद आए प्रभास मुखर्जी ने 2005 से 2010 के बीच रेल कंपनियों को कौमन नहीं बढ़ाने के कारण हुए घाटे को भरपाई सीधे सिविली टैकर नहीं को बलिका 1.34 लाख करोड़ रुपये के तैल बॉन्ड जारी कर दिए। उर्वरक कंपनियों के लिए भी इसी वजह से उर्वरक बॉन्ड जारी किए गए। इस तरह के बॉन्ड जारी करने की कोई जानकारी 2008-09 तक बजट में नहीं दी गई।

युवाविस्मृति से 2010-11 में यह राजकोषीय नासमझी बंद हो गई। परंतु खजाने पर इन बॉन्ड का बोझ ब्याज की हद तक में आया, जो एक के बाद एक सरकारी को परेशान करता रहा। चतुर्धा सरकार को भी यह बोझ उठाना पड़ा है। मोदी सरकार ने भी सरकारी बैंकों के पुनर्गठनीकरण के लिए बॉन्ड जारी किए, जिस पर सरकार खला किया जा सकता है। मगर अपने कम से कम खुलासा तो किया है और सभी को बताया है कि ब्याज और मूलधन चुकाने में अगले कुछ वर्षों तक किन्तु रकम जायगी में अगले कुछ वर्षों तक किन्तु का बोझ प्रतिष्ठा के वित्त मंत्रियों और सरकारी पर खलना राजकोषीय दृष्टि से नर निस्कार्यमाना कदम होता है और बिना जानकारी दिए किया जाए तो और भी नासमझक होता है।

यूक्रेन 2024-25 के बजट में पहली बार 2023-24 के व्यवस्थापक वक्तव्य के प्रमुख अंक शामिल किए गए हैं, जो जुलाय में बजट तैयार करते समय आ गए थे। ताजगीनर अकेदों का इस्तेमाल सहायक है। परंतु बजट दस्तावेज में वक्तव्य 27-ए को शामिल करना भी सहायक है, जबकि एफआरबीएम अभिनियम के मुताबिक ऐसा करना कोई आवश्यकता नहीं है।

उम्मीद करनी चाहिए कि यह वक्तव्य अपने पहले वर्षों में भी बजट में शामिल करके सरकार और लोकनीति पर टिप्पणी करने वाला बकाया देवदारी में किसी भी अन्वेषणाधिक उल्लेख को और ध्यान दिला सके और सरकार उसे चेतानवी मानकर जल्दी कदम उठा सके। वॉल्यूमिक वित्तीयधियों में लंबे सरकारी स्वामित्व वाले भी वॉल्यूमिक निष्कारों की बकाया देवदारी को भी शाहद इन वक्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे अधिक ठीक से साबित स्वरूप दिया जा सके।

पड़ोसी देशों से खत्म होते मित्रतापूर्ण संबंध

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने तैर पर शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के शर्मिंदगी पर अंत ने देश के भविष्य को अभिप्रेतता में झुक दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक परिणाम यह भी हुआ है कि दक्षिण एशिया में भारत अलग-थलग पड़ गया है। इस बात पर मजबूत हो सकते हैं कि भारत के नीति निर्माता अपने पुनर्गठन तरीके से हसीना का समर्थन क्यों करते रहे, जबकि यह स्पष्ट हो चुका था कि उनका लोभाप्रियता तैजो से ही घट रही है। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसा किया और उसी का परिणाम है कि उनका भारत-बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश के नेता का खुला समर्थन किया जाना अधिकतम मामलों में अलग फैसला हो सकता है, लेकिन इस गलती को ठीक करना भी आसान होता है। किन्तु भारत और बांग्लादेश के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही पेचीदा है क्योंकि यह नया पुरा पर निर्भर है कि बांग्लादेश के नार्मल अपने देश के कौन सी विचारधारा चुनते हैं।

बांग्लादेश में भारत को ऐसे निष्पक्ष और तटस्थ पदोसी के रूप में देखा जाता है, जो जरूरत पड़ने पर यह मदद माने पर हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस गलती को बतबरक का भागीदार मानना है। इससे उर देश के भीतर ऐसा राजनीतिक माहौल बनता है, जिसमें 1971 के जन्मे - सांस्कृतिक आजादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा राजनीतिक माहौल बनता है, जिसमें भारत को देखल देने वाला खतरा मान लिया जाए तो बांग्लादेश के लोग अपने देश को और अलग-

थल रचना चाहें तथा धार्मिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ें। यह वास्तव में बहुत ही खतरा है कि बांग्लादेश की ओर बढ़ने के बाद भी हसीना सरकार को भारत के स्पष्ट समर्थन में बांग्लादेश में ऐसे राजनीतिक बदलाव की स्थिति पैदा करे, जो, ओरों जाकर उर देश के साथ भारत देश को भी नुकसान पहुंचाए।

इसलिए यह बेहतर दृष्टिकोण होगा कि भारत देश में अधिकतम ध्यान से कुछ हासिल नहीं हुआ है। भारत से पड़ोसी देशों में सतार हुए लोगों के पथ में बोलता है तो अच्छा लगता है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश के हिंदू समुदायों के कई सदस्यों पर एलिसा हत्या किए गए हैं। लेकिन यह बात बेहद अतिरिक्त लगती है कि उर देश छात्रों का नारासह हुआ यह देश के राष्ट्रीय विमर्शों के यह मुद्दा समर्थन गायब रहा और अब यह उधार गया है।

बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारना हमारे देश को प्राथमिकताओं में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को देश में व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसकी मदद भी की जानी चाहिए। सारा ही अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और बांग्लादेश पिछले दो चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है।

भारत के लिए यह बात कतना कुछ मुश्किल हो

सकता है क्योंकि पिछले चुनाव निष्पक्ष नहीं होने पर उरने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा। फिर भी भारत को ऐसा तर्क चाहिए कि देश अगला चुनाव भी पारदर्शित समर्थ लेकर करेगा जाना चाहिए ताकि नई सरकार को बांग्लादेश के संस्थापकों के बेहतरों के लिए काम करने का समय मिल सके। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शित समर्थ भी मिल जाए कि अगली बार या लोग की भरपाई और विचारधारा को लेकर अपने वाली कोई भी पार्टी चुनावों में भागीदारी कर सके और पार्टी के मामले में अपनी सच्ची ताकत को निष्पक्ष तरीके से परख सके।

तक बुद्धि तो यह करनी है कि बांग्लादेश घटनाक्रम के बाद हमारे देश में इस बात पर गंभीर विचार होना चाहिए कि हमारी नीतियों में क्या परिवर्तन लें हैं। क्या हमारे विचारों को बदलना है जो बांग्लादेश के साथ अछे संबंध बनाने के लिए हमें अनिवार्य रूप से करने के लिए हैं। बांग्लादेश के साथ व्यापार और कारोबार इतिहास तैजो से बढ़ना चाहिए था, उरना नहीं बढ़ पाया है। कुछ पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों को हमने मदद की मगर कभी-कभार उर मदद के कारण विवाद को स्थिति बन गई है। बिना परिशोनाओं का वादा हमने पड़ोसीयों से किया, उनकी प्रगति भी बहुत धीमी है और कई बार लगता है कि इसके कारण स्थानीय स्तर पर अंधधुंध होना होगा।

पुटिन को छोड़कर इस बहुत ही गंभीर परिणाम में भारत के दोस्ताना तालुकका अपेक्षाकृत कम है। क्या इससे कोई फायदा है? या शाहद नहीं, क्योंकि भारत बड़ा देश है। लेकिन शायद फक पड़ता है। कुछ ही देश हैं, जो पड़ोसीयों के साथ मित्रता नहीं होने पर भी अपनी बुद्धि तथा विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाए हैं। इस नाकामी के लिए किन्तु जिम्मेदार ठहराया जाएगा है।

आपका पक्ष

चिकित्सा बीमा के निधम सभों के लिए पारदर्शी कैसे सरकार द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयुध्यान भारत प्रधानमंत्री उर आरोग्य योजना के अंतर्गत छह करोड़ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक बीमा योजना का लाभ सहायक पहल है। केंद्र सरकार ने यह घोषणा सभों नागरिकों और आयुधन के लिए समाप्त रूप से की है। यह भी आवश्यक है कि कानूनी रूप से संज्ञान को माना-पिता और परिवार के अन्य बहू उर और अशक्त परिवारों को देवभाल की वाज्यता हो। दीर्घकालिक परिप्रेष्य में सरकार की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने पर इस योजना में भी बदलाव आ सकता है। ऐसी स्थिति के लिए समाज और शासन को अपनी वैकल्पिक व्यवस्था रखने की आवश्यकता है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बहू रोगियों के लिए जैववैद्य विभागा हो जहां अत्यंत बुढ़ रोगियों की चिकित्सा निमित्त रूप से हो सके। जो वाहद नागरिक



केंद्र सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए आयुध्यान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक बीमा सुविधा लाई है।

आयुध्यान भारत योजना के लाभ के योग्य न हो उनके लिए सभों निजी अस्पतालों में अस्पेशी और इन्डोर चिकित्सा के लिए अनुचित बहू मिलनी चाहिए। बीमित रोगी को चिकित्सा का खर्च

रोगी को हदय, लीवर और किडनी की बीमारियों साधारण बात है। इसलिए केवल मधुमेह तक बीमा सीमित करना मोड़कल दृष्टि से भी अनुचित है। समग्र रूप से चिकित्सा बीमा क्षेत्र में व्यवस्था को समावेश और पारदर्शी तथा रोगियों के लिए विकार रहना चाहिए।

विनोद जीवरी, दिल्ली

शारीरिक गतिविधि स्वास्थ्य के लिए जरूरी शारीरिक गतिविधि अछे स्वास्थ्य के जूड़ी है। यह बात ऐसे समय में सच नहीं हो सकती जत युवा अधिकतम स्क्रीन समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करते हैं और बाहरी मनोरंजक गतिविधियों में कम समय बितते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि भारतीय अरुण दोस्तरियों या अपने दूरगोयी समकक्षों की तुलना में

फिटनेस वर्कशॉप में भी स्थान नहीं रखते हैं। चाहे उन जागरूकता की कमी के कारण स्थिति प्रतिकूल हो या उनकी तकनीकी समझ या निर्यात व्यापार के बजाय आराम जाहने वाली मानसिकता के कारण, वास्तविक डेटा चौंकाने वाला है। डेल बर्ग पंडाडजर्स, एशिया पैसिफिक और सोसाइटी एक्सप्लोरर द्वारा खेले और शारीरिक गतिविधि पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण बताता है कि 20 करोड़ भारतीय डेस्कपुचओ हारा निष्पक्षता में निष्कर्ष है। वयस्ककों को सराहा में 150 मिनट और बच्चों और किशोरों का प्रतिदिन 60 मिनट की गतिविधि की आवश्यकता होती है। कई एनजीओ और निजी कंपनियों खेलों को प्रोत्साहित कर रही हैं। खेलों इंडिया, योग जैसे भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, वकआउट के माध्यम से अतिरिक्त भारी उपकरण के प्रयोगों को आसरात करने के लिए सकारात्मक कदम है।

देश-दुनिया

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डोभाल ने रुस के सुरक्षा सलाहकार सर्गी शोवगु से भी मुलाकात की और यूक्रेन तथा रुस के बीच संघर्ष को समाप्त करने में भारत की निर्यात भूमिका पर चर्चा की। डोभाल ने पुतिन को 'अनेक मुद्दों पर बातचीत की। डोभाल-शोवगु मुलाकात विश्व (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के एक सम्मेलन से इतर हुई।

कोरो - पीटीआई

पाठक अपनी राय हमें इस पृष्ठ पर भेज सकते हैं: संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बाहुदुर शाह जंकर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं: lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

विजय सिंह अग्रवाल, नैनीताल

